

प्रेषक,

डा० राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून दिनांक: 06 अगस्त, 2009

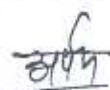
विषय: वित्तीय वर्ष 2009-10 में माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिला योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 515/XXVII(1)/2009; दिनांक: 28 जुलाई, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि को सम्मिलित करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन जिला योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या: 11 के अधीन आयोजनागत पक्ष में रु० 782.50 लाख (रुपये सात करोड़ बयासी लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. जिला योजनान्तर्गत उन योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक: 28 जुलाई, 2009 के प्रस्तर-7 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित है, जिनमें तत्काल अथवा भविष्य में पद सृजन निहित है।
2. निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की समय सारिणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके। साथ ही वित्त विभाग के आदेश संख्या: 475/XXVII(1)/2008 दिनांक: 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेन्सी से एमओयू आवश्यक किया जाय।
3. प्रयोगशाला/अतिरिक्त कक्षा-कक्ष कॉमनरूम एवं पेयजल तथा शौचालय हेतु धनराशि जनपद-स्तर पर निर्धारित आगणन के आधार पर किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृति किये जा रहे कार्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा तथा उनकी कोई देयता आगामी वित्तीय वर्ष के लिए शेष नहीं रखी जायेगी।
4. निर्माण कार्यों के लिए निर्माण एजेन्सी का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण एजेन्सी के अभियन्ता उत्तरदायी होंगे। गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु यथा आवश्यक थर्ड पार्टी जांच भी करायी जाए।
5. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो०नि०वि० द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
6. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपर्युक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

क्रमशः...2



- 8 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 2047/XIV-219(2006) दिनांक: 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- 9 यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय-व्यय में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय-व्यय के प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक- 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01- सामान्य शिक्षा, 202- माध्यमिक, 00-आयोजनागत, 91-जिला योजना के सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 515/XXVII (1)/2009; दिनांक: 28 जुलाई, 2009 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

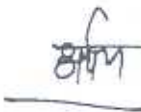
भवदीय

/

(डा० राकेश कुमार)
सचिव।पृष्ठांकन संख्या: 1184(1)/XXIV-3/09/02(34)2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा० शिक्षामंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
7. अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. समस्त जिला शिक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ।
11. बजट एवं राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर।
12. कम्प्यूटर सैल (वित्त विभाग)।
13. एन०आई०सी० सचिवालय परिसर।
14. सम्बन्धित निर्माण एंजेन्सी।
15. रक्षित पत्रावली।



आज्ञा से,

 (पी०एस० शाह)
 उप सचिव।

वै.सं.

शसनादेश संख्या: 1184/XXIV-3/09/02(34)09 दिनांक 06 अगस्त 2009 का संलग्नक

(घनसंशि लाख रुपयों में)

जनपद	लेखा शीर्षक 4202- शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01- सामान्य शिक्षा, 202- माध्यमिक शिक्षा, 91- जिला योजना			
	9101-राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन के लिए सुविधा तथा नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण	9102-राजकीय उ.मा. विद्यालयों / इण्टर कालेज -बालक/ बालिका के अधरे भवनों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	9103-राजकीय मा. विद्यालयों का भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि/भवन कय तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	9104-जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण
नैनीताल	13.20		3.50	13.40
ऊधमसिंहनगर	64.00		13.25	
अल्मोडा	63.20	16.00	24.50	3.45
पिथौरागढ़	11.00		8.00	
बागेश्वर	39.50			2.76
चम्पावत		16.50	31.50	
देहरादून	26.40		23.00	2.35
पौड़ी	70.50		22.75	17.80
टिहरी	55.75		33.50	
चमोली	110.30		18.25	8.98
उत्तरकाशी	19.80		10.25	
रूद्रप्रयाग	17.60		11.50	
हरिद्वार	8.75			1.28
योग	500.00	32.50	200.00	50.00

(कुल रुपये सात करोड बयासी लाख पचास हजार मात्र)

अभि



(पी.ओ. शाह)

उप सचिव